शहर की जनता से रिश्ता
छत्तीसगढ़ का पहला मिड-डे अखबार
हिन्दी दैनिक
जो दिखेगा वो छपेगा

METRO

» रायपुर, शनिवार 12 जनवरी 2019 » पौष शुक्ल पक्ष, षष्ठी

पेज 4 सीएम के हाथों छग सरकार...

डीजीपी अवस्थी के दरबार में मुरादें हो रहीं पूरी...

रायपुर (जसेरि)। प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार के सत्ता संभालने के साथ ही पुलिस कर्मियों को सौगात के रूप में साप्ताहिक अवकाश मिलने वाला है। वहीं उनके परिजनों के लिए नए डीजीपी ने डीएम अवस्थी दरबार लगाकर पुलिस कर्मियों के परिजनों की समस्या का समाधान शुरू कर दिया है। पुलिस कर्मियों के परिजनों की मुराद डीजीपी के दरबार में पूरी हो रही है जिससे उनके परिवार को झंझावत से सुकून मिलना शुरू हो गया है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर में राज्य भर से आये पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने विभिन्न जिलों से लगभग 400 से अधिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं पर शासकीय नियमों के अनुरूप जल्द निराकरण किया जायेगा।

पुलिस महानिदेशक अवस्थी को इस मौके पर बस्तर अंचल से आये पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों ने आरक्षक और सहायक आरक्षकों पद की वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी, इस पर उन्होंने वेतन विसंगति का परीक्षण कराकर शासन स्तर से निराकरण कराने के लिए आश्वस्त किया। अवस्थी के समक्ष बलौदा-बाजार जिले के प्रधान आरक्षक रतन लाल स्वाई ने पूर्व से गंभीर बीमारी में सर्जरी होने और शारीरिक तकलीफों के फलस्वरूप कार्यालयीन कार्य कराये जाने का आग्रह करने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक बलौदा-बाजार, भाटापारा को प्रधान आरक्षक की ड्यूटी मैदानी क्षेत्र से अलग करते हुए कार्यालयीन कार्य कराये जाने के निर्देश दिऐ।

समस्याएं लेकर पहुंचे जवानों के परिजनों को मिली राहत

डीजीपी अवस्थी ने रामानुगंज-बलरामपुर (सरगुजा) जिले के 12वीं वाहिनी के आरक्षक स्वर्गीय अजय एक्का की पुत्री कुमारी अनुष्का एक्का को पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 60 के तहत जिला रायगढ़ में रिक्त बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि डीजीपी अवस्थी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार के दिन पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों एवं उनके परिजनों से मिलने का दिन निर्धारित किया है।

पुलिस वालों के साप्ताहिक अवकाश पर एमपी से लेंगे फीडबैक

पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में सभी जिलों के एसपी व बटालियन के कमांडेंट ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि मध्यप्रदेश से भी साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में बनाई गई नीति मंगाई जाएगी। मध्यप्रदेश की नीति के अच्छे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे पुलिसकर्मियों की समस्याएं जानने के लिए 14 व 15 जनवरी को हर जिले से आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर को बुलाया गया है।

पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को डीआईजी नेहा चंपावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक अवकाश व पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी की बैठक हुई। इसमें समिति के सदस्य डीआईजी संजीव शुक्ला, आरिफ शेख, कवर्धा एसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह आदि भी शामिल हुए। कमेटी ने जिलों व बटालियन से आए फीडबैक पर चर्चा की।

जिलों व बटालियन से जो जानकारी भेजी गई है, उसके मुताबिक वीकली ऑफ देने में कोई परेशानी नहीं होने का उल्लेख है। मध्यप्रदेश ने काफी पहले ही वीकली ऑफकी शुरुआत कर दी है, इसलिए वहां की नीति का भी अध्ययन किया जाएगा, जिससे वहां की बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल किया जा सके।

ताजा खबर

संक्षिप्त

स्कूल-कालेजों में और सुधरेगी अंग्रेजी भाषा की गुणवत्ता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में लंदन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर ग्लोबल नेटवर्क लियम विंट ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्कूल और कालेजों में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने, छात्र-छात्राओं के अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शासकीय विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने विंट का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए करते हुए उन्हें इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी, सेमुअल आनंदराज, सरस्वती सुधाकर और रायपुर नगर निगम की पूर्व महापौर किरणमयी नायक भी उपस्थित थी।

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा

रायपुर। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी भजन सिंह वनवासी को तीन अलग-अलग धाराओं में क्रमश: दो, तीन व दस वर्ष सश्रम(कुल 15 साल) कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालयीन सूत्रों ने बताया कि मूलत: मप्र के डिंडौरी जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भगनवारा निवासी भजन सिंह वनवासी ने दो साल पहले टिकरापारा थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले में अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की पतासाजी शुरू की। 15 सितंबर, 2017 को किशोरी को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छुड़ाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। किशोरी ने अपने विस्तृत बयान में आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने की जानकारी दी।

ईंट फैक्टरी का चौकीदार 9 लाख का सामान लेकर फरार

रायपुर। खरोरा थानाक्षेत्र के ग्राम मोतिमपुर खुर्द स्थित ईंट फैक्टरी से नौ लाख का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी और किसी ने नहीं, बल्कि फैक्टरी के चौकीदार दंपती ने की है। फैक्टरी संचालक की शिकायत पर पुलिस ने अपराध कायम कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खरोरा के वार्ड नंबर एक निवासी श्रीमती पायल अग्रवाल पति राकेश की सिद्धि इंटरप्राइजेस नाम से ग्राम मोतिमपुर खुर्द ब्रीक्स बनाने की ईंट फैक्टरी है। इस फैक्टरी की देखरेख मंदिर हसौद थानाक्षेत्र के ग्राम तुलसी निवासी चौकीदार कोमल निषाद और उसकी पत्नी सरोज करते थे। एक नग कटर मशीन कीमती 12 हजार, एक नग ग्राइंडर मशीन दो हजार रुपये, एक नग ड्रिल मशीन कीमत दो हजार, एक बाइक, डेढ़ हजार रुपये कीमत का 3 नग एमसीबी समेत कुल 8 लाख 99 हजार 5 सौ रुपये का सामान चोरी हो गया। है।

सरकार बनते ही सीएम ने लोगों से पूछा

आखिर क्या करें स्काई वॉक योजना का.. जनता ही बताए

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। स्काई वॉक और स्काई योजना को लेकर कांग्रेस पहले से मुखर रही है। कांग्रेस इसका लगातार विरोध करते आई है। अब सीएम ने गेंद जनता के पाले में डाल दिया है। इसके बारे में जनता, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, अधिकारी से हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसका क्या करे और स्काई योजना का भी भी बतायें, उसके भी लाखों मोबाइल पड़े हैं। ये दो चीज स्काई योजना और स्काई वाक का क्या करना है, ये बतायें।

जनता जो राय देगी उसके अनुसार फैसला लूंगा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्काई वॉक और स्काई योजना पर फैसला लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्काई वॉक का ढांचा खड़ा हो गया है। इस वजह से जनता से राय मांग रहा हूं। जनता जो राय देगी उसके अनुसार फैसला लूंगा। यह बात मुख्यमंत्री ने राजीव भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही। बघेल ने कहा कि स्काई योजना है जिसके तहत प्रदेश में मोबाइल बांटी गई। इसमें सरकार का पैसा खर्च हो चुका है। मैं अपने तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लूंगा। इन योजनाओं को क्या किया जाए। इस मुद्दे पर जैसे ही आम राय आएगी, उसके मुताबिक निर्णय लिया जाएगा।

87 करोड़ की लागत

शास्त्री चौक, जय स्तंभ चौक और अंबेडकर अस्पताल से बीच पैदल यात्रियों के लिए रमन सरकार ने स्काई वॉक की नींव रखी थी। 87 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। भाजपा सरकार ने इसका ठेका जीएस कंपनी को दिया था। इसे पूरा करने की मियाद फरवरी 2018 रखी गई थी। लेकिन ठेकेदार ने बीच में काम बंद कर दिया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने दूसरे ठेकेदार को यह काम दिया गया। अब इसकी मियाद बढ़ाकर मई-जून कर दी गई। अब लोगों को सालभर और ट्रैफिक जाम की परेशानी से दो चार होना पड़ेगा।

स्काई ने बढ़ा दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का टेंशन

स्काई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टेंशन बढ़ा दी है। खुद भूपेश बघेल ने इस टेंशन से निजात दिलाने के लिए सुझाव मांगे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीसीसी दफ्तर में प्रेस कांफ्रेंस ले रहे थे। उसी दौरान राजधानी में बने स्काई वाक को लेकर उनसे पूछा गया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद दिलचस्प अंदाज में दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये स्काई वाक का क्या किया जाये, इसके लिए हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, प्रबुद्धजन, नागरिकों से राय मांगकर कार्रवाई करने की बात कही। उसी जवाब में उन्होंने स्काई योजना के तहत बांटे गये मोबाइल को भी जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काई योजना का भी हजारों मोबाइल बचा हुआ है उसका भी क्या करें, ये बतायें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इतना पैसा खर्च कर स्काई वाक तो खड़ा हो गया है, इसका किया क्या जाये।

567 करोड़ की स्काई योजना फेल

रमन सरकार ने 50 लाख लोगों को स्मार्ट फोन बांटने की स्काई योजना बनायी थी, जिसकी कुल लागत 567 करोड़ रुपये थी। हालांकि ये योजना पूरी तरह फेल रही, और फोन में कई तरह की शिकायतें बांटने के साथ ही आने लगी। वहीं स्काई वाक की योजना करीब 90 करोड़ रुपये की थी, इस योजना का शुरू से ही कांग्रेस विरोध कर रही थी। लेकिन चंद लोगों को फायदा देने के लिए भाजपा सरकार ने स्काई वाक को शहर में बनवा डाला, जिसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है।

फ्लाई ओव्हर बनाया जाए...

स्काई वाक को लेकर '**जनता से रिश्ता**' ने राजधानी की आम जनता, ट्रैफिक विशेषज्ञ, बुद्धिजावियों, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, अधिकारियों से इसके सदुपयोग को लेकर चर्चा की। जिसमें सभी ने अपने विचार साझा कर सरकार को सुझाव दिया है कि शहर के अंदर बने इस स्काईवाक को फ्लाई ओव्हर के रूप में बदला जाना चाहिए इसके लिए इसमें ज्यादा फेरबदल की आवश्यकता नहीं होगी और सड़क के दोनों ओर एक-एक पिल्लर खड़ी कर फ्लाई ओव्हर बनाया जा सकता है। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

सीबीआई को नो-एंट्री पर सीएम बघेल बोले

जिसे मौत का भय नहीं, वो सीबीआई से क्या डरेगा?

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के छापा मारने व जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के निर्णय पर विपक्ष हमलावर है. पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने भूपेश सरकार के इस निर्णय पर तंज किया और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई से डर लगता है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने भी निशाना साधा. धरमलाल ने क?हा कि राज्य सरकार को कोई भी निर्णय करने से पहले मन को बड़ा कर लेना चाहिए।

विपक्ष के सवालों पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया. शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन रायपुर में सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा की. सीबीआई मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा- 'किसी भी जांच एजेंसी से डरने की जरूरत नहीं है. डॉ. रमन सिंह ने बहुत डराने का काम किया है. मुझे मौत से भय नहीं है. पहले भी कहा था. जिस आदमी को मौत का भय नहीं उसे सीबीआई का क्या डर.'

सीएम बघेल ने कहा कि सीबीआई का सामना हम कर चुके हैं. डॉ. रमन सिंह की सरकार में ही साल 2012 में इसी आशय का नोटिफिक्रेशन दिया था. उसी को हमने आगे बढ़ाया है. यदि उनकी स्मृति क्षीण नहीं हुई है तो उन्हें याद होगा. नान घोटाला मामले में एसआईटी जांच और इसका नेतृत्व विवादित अफ्सर एसआरपी कल्लूरी को दिए जाने पर सीएम बघेल ने बयान दिया। नान मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा. सीएम बघेल ने कहा कि हमने तो उन्हीं के प्रिय अधिकारी को जांच में लगाया है. फिर तकलीफक्यों हो रही है. स्काई वॉक निर्माण मामले में सीएम ने कहा कि जनता से राय लेकर इसपर निर्णय लिया जाएगा।

ई-टेंडरिंग घोटाला, सुपर सीएम का सुपर घोटाला

कैग रिपोर्ट में 4600 करोड़ के ई-टेंडरिंग घोटाले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम का सुपर घोटाला बताया है। उन्होंने संकेतों में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान प्रभावशाली रहे एक अफसर की भूमिका पर भी तंज कसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार के दौरान किस तरह भ्रष्टाचार होता रहा। उन्होंने कहा कि एक ही कम्प्यूटर से इतने बड़े पैमाने पर टेंडर होना ही अपने आप में घोटाला दर्शाता है। यह भाजपा सरकार के एक सुपर सीएम का सुपर घोटाला है, ऐसे घोटालों की हम जांच करते हैं तो इसे बदलापुर कह देते हैं।

गैस की अवैध रिफिलिंग मामले में कारोबारी पर केस दर्ज

रायपुर। गोलबाजार चूड़ीलाइन में अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले कारोबारी अनुराग गुप्ता के खिलाफपुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज कर लिया है। पिछले महीने खाद्य विभाग की टीम ने कारोबारी की दुकान में छापा मारा था, वहां से 25 सिलेंडर जब्त किए गए। खाद्य विभाग के अफ्सरों ने जांच की। जांच पूरी होने के बाद गुरुवार को गोलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। छापे के बाद से कारोबारी फ्रार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

ईओडब्ल्यू की अपील खारिज

नान घोटाला: सुनवाई रोकने से कोर्ट का इंकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले की सुनवाई रोकने की ईओडब्ल्यू की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा शासन में हुए करोड़ों के नान घोटाले की एसआइटी जांच शुरू हुई है। इसको लेकर ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में सुनवाई रोकने की अपील की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसआइटी 11 बिंदुओं पर जांच करने जा रही है। ईओडब्ल्यू की अपील परजेल में बंद नान घोटाला के आरोपित तत्कालीन प्रबंधक शिवशंकर भट्ट के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस मामले में एक साल में सुनवाई पूरी करनी है। अगर मामले की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो शिवशंकर भट्ट को मानसिक नुकसान होगा। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो(ईओडब्ल्यू) ने नान मामले में 16 आरोपियों के खिलाफचालान पेश किया था। बाद में दो आइएएस अधिकारियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया गया। प्रकरण में 70 गवाहों का बयान भी दर्ज किया जा चुका है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईओडब्ल्यू ने जांच के लिए जो आधार पेश किया है, उस पर जांच के लिए स्वतंत्र है। इस आधार पर कोर्ट की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती। ऐसे में ईओडब्ल्यू के आवेदन को निरस्त किया जाता है। ईओडब्ल्यू जांच के अलावा एसआइटी जांच में अगर कोई नया तथ्य सामने आता है, तो उसे पूरक चालान के रूप में पेश किया जा सकता है। चालान पेश होने के बाद भी जांच एजेंसी को जांच करने पर कोई रोक नहीं है लेकिन इसके लिए न्यायालय से अनुमति नहीं दी जा सकती है।

नान घोटाले में शिवशंकर भट्ट पिछले तीन साल से जेल में बंद हैं। आइएएस अनिल टुटेजा ने 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। 22 दिसंबर को टुटेजा का आवेदन ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक को भेजा गया है और उनसे बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया है।

सब्जी वालों ने शास्त्री बाजार में अवैध वसूली का किया विरोध

रायपुर। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की अवैध वसूली से परेशान होकर शुक्रवार को लामबंद सब्जी व्यापारियों ने शास्त्री बाजार में आंदोलन कर चक्काजाम किया। व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उगाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। आंदोलन के कारण देर तक सब्जी बाजार बंद रहा। इससे सब्जी खरीदने आए लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। रायपुर नगर निगम के शास्त्री बाजार हमेशा से विवाद में रहा है। शुक्रवार को सब्जी व्यापारी और निगम अधिकारी के बीच विवाद हो गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध वसूली करने के साथ कुछ लोगों की सब्जी जब्त कर चबूतरे तोड़ने की कोशिश की। इस कार्रवाई के विरोध में लामबंद सब्जी व्यापारियों ने शुक्रवार सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू कर शास्त्री मार्केट को घेरकर चक्काजाम कर दिया।

भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बनने होड़, हर बड़ा नेता दावेदार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही संगठन के निर्देश पर चलने वाली पार्टी कहा जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब करारी हार के बाद संगठन के पदों के लिए रोज नए दावेदार आ रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई दिग्गजों ने इशारों-इशारों में कह दिया है कि उनसे पूछा जाएगा तो वो दावेदारी जरूर करेंगे. भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द ही नाम का ऐलान हो सकता है।

भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है. पार्टी का अध्यक्ष एक ताकतवर पद होता है. ऐसे में कई दिग्गज इसे लेकर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं. पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को प्रबल दावेदार माना जा रहा था. हालांकि उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद यह तो साफ हो गया कि वो अब दावेदार की दौड़ से बाहर हो गए हैं. 11 और 12 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है जिसमें कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं।

दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में जब उनसे पूछा गया तो किसी ने भी दावेदारी से इंकार नहीं किया. हालांकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो डॉ. रमन सिंह का ही नाम ले लिया. आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष की बात होने पर केदार कश्यप ने भी अपनी बात रखने की बात कही. पूर्व मंत्री अजय चन्द्राकार, प्रेम प्रकाश पांडेय ने भी खुलकर नहीं कहा, लेकिन इशारों में कहा कि यदि दावेदारी की बात आएगी तो जरूर करेंगे। डॉ. रमन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं. वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि पार्टी में किसी तरह की दावेदारी की कोई परंपरा नहीं है. उन्होंने इस बात पर भी इंकार किया कि डॉ. रमन सिंह, जो तेजतर्रार दिख रहे थे सदन में वह विधानसभा नेताप्रतिपक्ष बनने की कवायद थी. जाहिर तौर पर यह बयान बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए प्रदेश अध्यक्ष तय करना इतना आसान नहीं है।